अरुंधति अशोक वालवलकर

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(सिविल अपील सं. 6966/2004 )

13 जनवरी, 2011

[डॉ. मुकुंदकम शर्मा और एंडिल आर. डेव, जे. जे।]

सेवा कानूनः

महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979-आरआर। 3 (iii), 5 (1) (vii)-न्यायिक द्वारा कदाचार अधिकारी-लोकल ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने के लिए आरोपित और अपने आधिकारिक पहचान पत्र का दुरुपयोग- निर्णित-अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा का औचित्य-सही। आरोप पत्र के अनुसार जो आरोप अधिकारी पर लगे है- उसके खुद के बताए अनुसार स्थापित- इस प्रकार- जांच अधिकारी द्वारा उस पर लगाए गए आरोप को प्रमाणित पाया जाना सही। उसकी स्थिति साबित हुई-उसे दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा उसके खिलाफ कथित अपराध के अनुपात से अधिक नहीं थी। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए

अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

न्यायपालिका-न्यायिक अधिकारी-आचार संहिता-निर्णित: न्यायाधीश का आधिकारिक और व्यक्तिगत आचरण योग्यता औचित्य और ईमानदारी के उच्चतम मानक का होना चाहिए।

आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता न्यायिक अधिकारी तीन बार लोकल ट्रेन में बिना टिकट यात्रा की और उसने उसके आधिकारिक पहचान पत्र का दुरुपयोग किया, उसे अनावश्यक रेलवे प्लेटफार्म पर हंगामा किया और रेलवे कर्मचारी को धमकियां दीं । उसके खिलाफ आरोप विरचित किए गए और अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपीलार्थी को महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण के नियम 3 (iii) के अन्तर्गत दुराचार का दोषी ठहराया एवं नियम 5 (1) (vii) के तहत अपीलार्थी को दण्ड के तौर पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया। अपीलार्थी द्वारा अनिवार्य सेवानिव्रत्ति के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए, अपीलार्थी ने तत्काल अपील दायर की।

न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया कि:-

1.1 उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है कि उसने वास्तव में उस दिन बिना किसी टिकट के यात्रा की थी और जब उसे दोषी ठहराया गया, तो उसने बस टिकट कलेक्टर के हाथों में पहचान पत्र दे दिया और चली गई जगह से दूर. रेलवे और विभागीय प्राधिकरण द्वारा पूछताछ में वही विशिष्ट रुख अपनाया गया। यदि उसका मामला यह था कि उसने अपना पहचान पत्र खो दिया है, तो उसके लिए तुरंत संबंधित प्राधिकारी या पुलिस के पास शिकायत दर्ज करना आवश्यक था जो उसने कभी नहीं किया। वास्तव में उक्त पहचान पत्र तीन दिन बाद रेलवे द्वारा उसे वापस कर दिया गया। यदि उसने उस दिन ट्रेन से यात्रा ही नहीं की थी तो '0' रेलवे स्टेशन पर पहचान पत्र बरामद होने का कोई उचित कारण नहीं है। [ पैरा 16 और 17] [365-सी-ई]

1.2 जहां तक 13.5.1997 की घटना का सवाल है, अपीलकर्ता का विशिष्ट बचाव यह है कि उसने 13.5.1997 को प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा था, लेकिन ट्रेन में चढ़ते समय वह खो गया, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। यह अत्यधिक असंभाव्य है क्योंकि उसने स्वेच्छा से यह कहते हुए शुल्क का भुगतान किया था कि बिना टिकट यात्रा करने वाले मजिस्ट्रेट को जुर्माना देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। तथ्य यह है कि 13.5.1997 को भी अपीलकर्ता कोई वैध टिकट या पास प्रस्तुत नहीं कर सका, जब उसे रोका गया और वैध टिकट/पास प्रस्तुत करने के लिए

कहा गया। ट्रेन में चढ़ने के दौरान उसका टिकट खो जाने का बचाव हमेशा कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसे बयान का समर्थन करने के लिए कुछ बुनियादी तथ्य होने चाहिए जो कि तत्काल मामले में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जा सके। [ पैरा 18] [365-जी-एच; 366-ए बी]

1.3 5.12.1997 की घटना के संबंध में, इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उस विशेष दिन, वह 'एम' स्टेशन 8 पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे में चढ़ी, हालांकि उसके पास कोई वैध टिकट/पास नहीं था। उसने जुर्माना अदा किया जो उसे उसके एक सहकर्मी ने दिया था। बाद में उसने यह रुख अपनाया कि उसने एक सीज़न टिकट खरीदा था, लेकिन उक्त टिकट भी 'डी' स्टेशन पर खरीदा गया पाया गया। इसके अलावा, 5.12.1997 को, जब अपीलकर्ता को बिना टिकट के पकड़ा गया और जब उसे टिकट दिखाने के लिए कहा गया, तो वह ऐसा नहीं कर सकी और न ही वह इस आधार पर शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार थी क्योंकि वह एक मजिस्ट्रेट थी और इसलिए उसे बिना टिकट यात्रा करने का अधिकार था. रिकॉर्ड से यह स्थापित होता है कि बाद में, उसने 102/-. रुपये की राशि का भुगतान किया। [ पैरा 19 और 20 ] [ 366 - सी-ई]

1.4 अपीलकर्ता द्वारा रेलवे महाप्रबंधक को लिखा गया पत्र और यह तथ्य कि वह एम और डी स्टेशन के बीच अपनी यात्रा के लिए कोई टिकट या पास नहीं दिखा सकी, स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करता है कि

5.12.1997 को उसने बिना टिकट के यात्रा की थी। मध्य रेलवे, मुंबई के महाप्रबंधक को लिखे उक्त पत्र में अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि कई बार वह समय की कमी के कारण टिकट खरीदने में असमर्थ होती है, जिसके लिए टिकट कलेक्टरों द्वारा उसे परेशान किया जाता है, इसलिए ऐसी आपात स्थिति के दौरान समय पर अदालतों तक पहुंचने के उद्देश्य से लोकल ट्रेनों के प्रथम श्रेणी डिब्बे में यात्रा करने के लिए उसे मुफ्त टिकट प्रदान किया जाना चाहिए। 5.12.1997 को घटना के तुरंत बाद लिखे गए एक पत्र से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उन्होंने 5.12.1997 को बिना टिकट के यात्रा की थी और उनसे टिकट की मांग करना उन्हें बुरा लगा क्योंकि वह एक मजिस्ट्रेट हैं और उन्होंने टिकट कलेक्टरों के खिलाफ शिकायत की थी। इसलिए, 5.12.1997 के आरोपों के ज्ञापन में अपीलकर्ता के खिलाफ लगाया गया अपराध उसके स्वयं के दिखाने पर स्थापित होता है और इसलिए, जांच अधिकारी का इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित था कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हुए हैं। [ पैरा 23 और 24] [367-जी-एच; 368 ए-बी]

2.1 महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के नियम 8(25)(ई) ने एक जांच अधिकारी को मामले के तथ्यों में प्रदान की जाने वाली सजा की सिफारिश करने की अनुमति दी। [ पैरा 26 ] [ 368 - डी]

2.2 रिकॉर्ड देखने पर यह पाया गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर विचार किया और उसके बाद, एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ता अपने खिलाफ लगाए गए कदाचार के आरोपों का दोषी है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसा बड़ा जुर्माना केवल उन पर ही लगाया जा सकता था और परिणामस्वरूप ऐसी सजा देने का निर्णय लिया गया। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाने के साथ ही संपूर्ण अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त हो गई। [ पैरा 27] [ 368 - एफ-एच]

2.3 यह दलील कि अपीलकर्ता को दी गई सजा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से असंगत है और उसे कम से कम उसकी पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, जो उसे दो साल तक काम करने की अनुमति देने पर दी जा सकती थी; और यह कि अपीलकर्ता ने 8 साल की सेवा पूरी कर ली है और यदि उसने दो साल और काम किया होता, तो वह 10 साल की अतिरिक्त सेवा के साथ पेंशन की हकदार होती, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सजा की मात्रा में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब दी गई सज़ा अदालत की अंतरात्मा के लिए चौंकाने वाली पाई गई। [ पारस 28,29] [369-ए-सी]

2. मौजूदा मामला न्यायिक अधिकारी का है, जिसे न्यायिक अधिकारी बनने के लिए गरिमा और शिष्टाचार के साथ आचरण करने की

आवश्यकता थी। एक न्यायिक अधिकारी को त्रुटिहीन आचरण दिखाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम होना चाहिए। मौजूदा मामले में, उसने न केवल तीन बार रेलवे में बिना टिकट यात्रा की, बल्कि टिकट कलेक्टरों के खिलाफ भी शिकायत की जिन्होंने उसे बिना टिकट होने से रोका, रेलवे अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन परिस्थितियों में उसे दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा के बारे में नहीं कहा जा सकता कि यह सजा उसके खिलाफ कथित अपराध से असंगत है।[ पैरा 29 ] [ 369 - सी-ई]

2.5 कानून के शासन द्वारा शासित देश में, न्यायिक अधिकारियों सहित कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। वस्तुतः न्यायिक अधिकारी के रूप में उन्हें प्रत्येक आचरण में गरिमा का सतत पहलू प्रस्तुत करना होता है। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तत्वावधान में कानून के शासन को प्रभावी ढंग से और कुशलता से कार्य करना है, तो न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि, बल्कि, उन्हें खुद को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करके एक कुशल और प्रबुद्ध न्यायपालिका का पोषण करना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि एक न्यायाधीश लगातार सार्वजनिक और समाज की नजरों में रहता है। एक न्यायाधीश से आचरण और सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों की अपेक्षा करता है। न्यायिक कार्यालय; सर्वसाधारण के विश्वास का कार्यालय होने के नाते, समाज को यह अपेक्षा करने का अधिकार है कि एक न्यायाधीश को प्रत्येक कार्य में औचित्य के सबसे सटीक मानकों को बनाए

रखते हुए उच्च सत्यनिष्ठा, ईमानदार और नैतिक दृढ़ता वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए, एक न्यायाधीश का आधिकारिक और व्यक्तिगत आचरण औचित्य और ईमानदारी के उच्चतम मानक के अनुरूप होना चाहिए। जाहिर है, आचरण का यह मानक दूसरों के लिए स्वीकार्य या स्पष्ट समझे जाने वाले मानकों से ऊंचा है। दरअसल, मौजूदा मामले में, एक न्यायिक अधिकारी होने के नाते, यह उनके हित में था कि वह खुद को शालीन और गरिमापूर्ण तरीके से पेश करें। यदि उसने जानबूझकर इन उच्च और सख्त मानकों से हटना चुना है, तो वह उचित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। [ पैरा 29] [369-एफ-एच; 370-ए-बी]

3. अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्वीकार किए जाते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय का कारण बताते हुए निकाले गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, जिससे वे पूरी तरह सहमत हैं और औचित्य पाते हैं। [ पैरा 30] [370-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: की सिविल अपील संख्या 6966/2004

बॉम्बे उच्च न्यायालय, की रिट याचिका संख्या 20/2001 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 13.04.2004 से।

सी.यू. सिंह, के.के. त्यागी. इफ़्तेख़ार अहमद, एन. अन्नपूर्णानी। बिपिन जोशी अपीलकर्ता की ओर से।

अनिरुद्ध पी. माई, चारुदत्त महिंद्राकर, एस.जे. पाटिल, संजय वी. खर्डे, आशा गोपालन नायर उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश डॉ.मुकुंदकम,शर्मा जे. द्वारा पारित किया गया :-

1. यह अपील यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई थी, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने के फैसले और आदेश से व्यथित थी।

2. अपीलकर्ता द्वारा इस अपील में जो मुद्दा उठाने की मांग की गई है वह यह है कि क्या महाराष्ट्र सिविल सेवा के नियम 5(1)(vii) के संदर्भ में अपीलकर्ता पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा लगाना अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उचित था। अनुशासन और अपील) नियम, 1979 इस आधार पर कि उक्त अपीलकर्ता-मजिस्ट्रेट को तीन बार लोकल ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पाया गया और प्रत्येक अवसर पर, रेलवे कर्मचारियों के साथ उक्त अपीलकर्ता-मजिस्ट्रेट के व्यवहार पर जोर दिया गया कि मजिस्ट्रेट को इसकी आवश्यकता नहीं है। टिकट लेना अनुचित था और गंभीर कदाचार है।

3. अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप यह था कि उसने 21.2.1997, 13.5.1997 और 5.12.1997 को बिना टिकट यात्रा की थी जब वह पकड़ी गई थी।यहां आरोप न केवल बिना टिकट यात्रा की ऐसी घटनाओं से

संबंधित थे, बल्कि उनके आधिकारिक पहचान पत्र का दुरुपयोग करने और रेलवे प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक दृश्य बनाने और रेलवे कर्मचारियों को धमकियां देने से भी संबंधित थे, जिसे नियम के अनुसार न्यायिक अधिकारी के लिए अशोभनीय कदाचार माना गया था। महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियम, 1979 के 3(iii)।

4. आरोपों की गंभीरता को समझने के लिए और चूंकि अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील की दलील थी कि वह बिना टिकट यात्रा के लिए जिम्मेदार नहीं थी, इसलिए हमें आरोपों के ज्ञापन जारी करने के लिए पृष्ठभूमि तथ्यों को बताना होगा। उसके खिलाफ.

5. 28.5.1992 को, अपीलकर्ता को बॉम्बे में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था।रेलवे अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ 21.2.1997, 13.5.1997 और 5.12.1997 को हुई तीन घटनाओं के लिए आरोप लगाए गए थे।जब अपीलकर्ता 5.12.1997 को मुलुंड में ट्रेन में चढ़ी, तो मुलुंड से दादर की यात्रा के दौरान दो टिकट कलेक्टरों ने उससे मुलाकात की, जिन्होंने उससे टिकट या अपना पास दिखाने के लिए कहा। हालाँकि, अपीलकर्ता ने कहा कि उसने सीज़न पास खरीदने के लिए अपने अर्दली पैसे दिए थे, जो दादर रेलवे स्टेशन पर बनाया जाएगा।यहां तक कि दादर रेलवे स्टेशन पर भी, जब उससेमुलुंड से दादर तक बिना टिकट यात्रा करने के लिए रेलवे किराया और जुर्माना भरने के लिए कहा गया, तो वह

स्टेशनों के बीच यानी मुलुंड से दादर तक की यात्रा के लिए कोई टिकट नहीं दिखा सकी।हालाँकि, अगली ट्रेन से यात्रा कर रहे एक अन्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दादर स्टेशन पहुंचे और अपीलकर्ता की दुर्दशा के बारे में सूचित किए जाने पर, वह स्टेशन अधीक्षक के पास आए और अपीलकर्ता को रुपये दिए।102/- का भुगतान अपीलकर्ता द्वारा रेलवे अधिकारियों को एक रसीद के बदले किया गया था। उक्त तिथि से पहले भी, यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने दो तिथियों यानी 21.02.1997 और 13.5.1997 को बिना टिकट यात्रा की थी।

6. रेलवे अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए उपरोक्त आरोपों की प्राप्ति पर, एक प्रारंभिक जांच की गई, जिसके पूरा होने पर 25.3.1998 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कहा गया कि उपरोक्त तीन तारीखों पर अपीलकर्ता द्वारा बिना टिकट यात्रा की घटनाएं हुईं। अपीलकर्ता के विरूद्ध मामला कायम किया गया था।

7. इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों का एक ज्ञापन तय किया गया और उसे 17.12.1998 को जारी किया गया। अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों की दो विशिष्ट धाराएँ तय की गईं जो निम्नलिखित प्रभाव वाली थीं: -

क. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मजिस्ट्रेटों को टिकट खरीदने या पास लेने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें ड्यूटी पर जाने के उद्देश्य से

किसी भी यात्रा प्राधिकरण के बिना किसी भी स्थानीय ट्रेन में प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति है।

ख. याचिकाकर्ता को बिना टिकट/यात्रा प्राधिकरण के लोकल ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में यात्रा करने के लिए तीन बार पकड़ा गया और जब पकड़ा गया तो याचिकाकर्ता ने टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ बहस की और 05.12.1997 को लगभग 10:30 से 11 बजे सुबह हंगामा खड़ा कर दिया। और दादर रेलवे स्टेशन पर टिकट संग्राहकों को धमकी दी जब अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता बिना टिकट यात्रा करने के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करें।

8. उपरोक्त आरोपों के ज्ञापन के साथ, गवाहों की सूची के साथ आरोपों की सूची के साथ कदाचार के आरोप के बयान के साथ आरोपों की धाराएं अपीलकर्ता को भेज दी गईं।

9. अपीलकर्ता की उपरोक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही दो अन्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्थात् श्रीमती रमा वाघुले और श्री वीवी फांड के साथ की गई थी।चूँकि हम अन्य दो अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों से चिंतित नहीं हैं, इसलिए हम वर्तमान मामले में इसका उल्लेख करने से बचते हैं।

10. उपरोक्त आरोपों के ज्ञापन की प्राप्ति के बाद, अपीलकर्ता ने एक निश्चित रुख अपनाते हुए अपना जवाब भेजा कि 21.2.1997 को बिना

टिकट यात्रा कीकथित घटना जानबूझकर मनगढ़ंत और काल्पनिक थी, जबकि बिना टिकट यात्रा की शेष दो घटनाओं के संबंध में, यह कहा गया थाउनके द्वारा कहा गया कि ऐसा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण था जैसा कि विशेष रूप से उक्त उत्तर में बताया गया है।

11. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संदर्भ में विभागीय जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया।विस्तृत जांच करने और कई गवाहों की जांच करने के बाद, जांच अधिकारी ने 28.10.1999 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हुए हैं।जांच अधिकारी ने माना कि अपीलकर्ता को कम से कम तीन बार बिना टिकट यात्रा करते हुए पाया गया और प्रत्येक अवसर पर उसका व्यवहार उचित नहीं था और न्यायिक अधिकारी के व्यवहार के अनुरूप नहीं था।जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिपोर्ट पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों वाले अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया और अपीलकर्ता को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया।

नतीजतन, अपीलकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें उसे यह बताने के लिए कहा गया कि जांच अधिकारी द्वारा

दर्ज किए गए निष्कर्षों को क्यों स्वीकार नहीं किया जाएगा और अपीलकर्ता पर सेवा से बर्खास्तगी सहित बड़ा जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाएगा।

12. अपीलकर्ता ने 24.01.2000 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमेंअनुरोध किया गया कि उसे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अपनी और तीन स्वतंत्र गवाहों की जांच करने की अनुमति दी जाए।हालाँकि, उक्त आवेदन को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ा दिया, जिसके बाद उसने 9.3.2000 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया।उपरोक्त उत्तर प्राप्त होने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उसके मामले पर विचार किया और निर्णय लिया कि वह कदाचार की दोषी थी और इसलिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया और परिणामस्वरूप दिनांक 27.9.2000 को अपीलार्थी के विरूद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया गया।

13. पारित आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के उपरोक्त आदेश की वैधता और वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

14. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने, जैसा कि पहले कहा गया था, रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसके खिलाफ वर्तमान अपील दायर

की गई थी।जब मामला सूचीबद्ध किया गया था, तो हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना और अपीलकर्ता के अपराध के संबंध में एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया और बहुत सूक्ष्मता से उसकी जांच की।आगे बात करने से पहले वर्तमान मामले के कुछ प्रासंगिक तथ्यों की जांच करना उपयोगी होगा।तीन घटनाएं हैं जिनके आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ कदाचार के आरोप तय किए गए थे।उक्त घटनाएँ 21.2.1997, 13.5.1997 और 5.12.1997 को थीं। जहां तक 21.2.1997 को बिना टिकट यात्रा करने की घटना का सवाल है, यह रेलवे और अनुशासनात्मक प्राधिकारी का मामला है कि उसने उक्त तिथि को बिना टिकट यात्रा की थी और जब उसे अपना पास या टिकट दिखाने के लिए कहा गया, उसने बस अपना पहचान पत्र टिकट कलेक्टर के हाथों में दे दिया और शारीरिक रूप से पकड़े जाने से पहले वह चली गई।हालाँकि, अपीलकर्ता का उपरोक्त पहचान पत्र रेलवे अधिकारियों द्वारा 24.2.1997 को उसे वापस कर दिया गया था। उपरोक्त घटना पर एक आरोप लगाया गया था जिसके खिलाफ उसने स्पष्ट बचाव किया था कि उसने अपना आधिकारिक पहचान पत्र खो दिया था और सूचना मिलने पर कि वह दादर रेलवे स्टेशन पर पाया गया था, उसने इसे रेलवे अधिकारियों से एक कांस्टेबल के माध्यम से एकत्र किया था। 24.2.1997.उक्त आरोप के खिलाफ विभागीय कार्यवाहीमें उनका विशिष्ट मामला यह था कि उन्होंने 21.2.1997 को कभी भी ट्रेन से यात्रा नहीं की थी।

15. जहां तक उक्त बचाव का सवाल है, उच्च न्यायालय ने इसे बिना किसी आधार के पाया, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यदि अपीलकर्ता फरवरी, 1997 के महीने के दौरान कार में यात्रा कर रही थी, जैसा कि उसने कहा था। ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसका आधिकारिक पहचान पत्र दादर रेलवे स्टेशन पर पाया और खोजा जा सके। यह भी माना गया कि वह यह बताने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थीं कि दादर रेलवे स्टेशन पर उनका पहचान पत्र कैसे खो गया।यह भी माना गया कि चूंकि अपीलकर्ता की ओर से कोई सबूत नहीं दिया गया था और चूँकि 24.2.1997 को कथित तौर पर रेलवे अधिकारियों से पहचान पत्र एकत्र करने वाले कांस्टेबल सेउसके बचाव को स्थापित करने के लिए पूछताछ नहीं की गई थी, इसलिए उपरोक्त बचाव अपीलकर्ता द्वारा लिए गए फैसले को उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया और यह माना गया कि 21.2.1997 को बिना टिकट यात्रा करने का उक्त आरोप वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में साबित होता है।

16. हमें उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्षों से अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं मिलता है। जांच में रेलवे और विभागीय प्राधिकारी का विशिष्ट रुख यह है कि जब अपीलकर्ता पर बिना टिकट यात्रा करने का आरोप लगाया गया, तो उसने अपना पहचान पत्र टिकट कलेक्टर के हाथों में दे दिया और चली गई और टिकट कलेक्टर को उसे हिरासत में लेने का कोई मौका नहीं दिया।यदि उसका मामला यह

था कि उसने अपना पहचान पत्र खो दिया है, तोउसके लिए तुरंत संबंधित प्राधिकारी या पुलिस के पास शिकायत दर्ज करना आवश्यक था जो उसने कभी नहीं किया।उक्त पहचान पत्र वास्तव में रेलवे अधिकारियों द्वारा 24.2.1997 को उसे वापस कर दिया गया था।हमें दादर रेलवे स्टेशन पर पहचान पत्र बरामद होने का कोई उचित कारण नहीं मिल सका, अगर उसने उस दिन ट्रेन से यात्रा ही नहीं की थी।

17. उच्च न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है,उसके अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं हो सकता है कि उसने वास्तव में उस दिन बिना किसी टिकट के यात्रा की थी और जब उसे दोषी ठहराया गया,तो उसने टिकट कलेक्टर के हाथों में पहचान पत्र थमा दिया और वहां से चली गई।

18. जहां तक13.5.1997 की घटना का सवाल है, अपीलकर्ता का विशिष्ट बचाव यह है कि उसने13.5.1997 को प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा था लेकिन ट्रेन में चढ़ते समय वह खो गया जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। इसे अत्यधिक असंभावित माना जा रहा है क्योंकि उसने यह कहते हुए स्वेच्छा से शुल्क का भुगतान किया था कि बिना टिकट यात्रा करने वाले मजिस्ट्रेट को जुर्माना देने के लिए नहीं कहा जा सकता है।तथ्य यह है कि 13.5.1997 को भी अपीलकर्ता कोई वैध टिकट या पास प्रस्तुत नहीं कर सका, जब उसे रोका गया और वैध टिकट/पास प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।ट्रेन में चढ़ते समय उसका टिकट खो जाने

का बचाव हमेशा कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे चिंतित दृष्टिकोण में, ऐसे बयान का समर्थन करने वाले कुछ बुनियादी तथ्य होने चाहिए जो कि तत्काल मामले में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

19. जहां तक 5.12.1997 की घटना का सवाल है, हम पाते हैं कि इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उस विशेषदिन, वह मुलुंड स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे में चढ़ गई, हालांकि उसके पास वैध टिकट नहीं था/ उसके अधिकार में पारित करें.उसने जुर्माना अदा किया था जो उसे उसके एक सहकर्मी ने दिया था।बाद में उसने यह स्टैंड लिया था कि उसने सीज़न टिकट खरीदा था, लेकिन उक्त टिकट भी दादर स्टेशन पर खरीदा गया पाया गया।

20. 5.12.1997 को, जब अपीलकर्ता को बिना टिकट के पकड़ा गया और जब उसे टिकट दिखाने के लिए कहा गया, तो वह ऐसा नहीं कर सकी और न ही वह इस आधार पर शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार थी कि वह एक मजिस्ट्रेट थी और इसलिए उसका अधिकार है बिना टिकट यात्रा करना.रिकॉर्ड से यह स्थापित होता है कि बाद में, उसने 102/- रुपये की राशि का भुगतान किया।

21. इस संबंध में, हम उनके द्वारा 8.12.1997 को महाप्रबंधक, मध्य रेलवे, मुंबई को लिखे गए एक पत्र का भी उल्लेख कर सकते हैं।कथित पत्र कथित तौर पर उसके द्वारा लिखा गया था और यह इस प्रकार है: -

"मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कभी-कभी, मुझे अपने न्यायालय तक समय पर पहुंचने के लिए आपकी स्थानीय ट्रेनों में प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि हमें जो वाहन दिया जाता है वह पूलिंग वाला होता है, जिसमें सड़कों पर अप्रत्याशित यातायात के कारण बहुत लंबा समय लगता है, या खराब हो जाते हैं"

ऐसे मौकों पर समय की कमी के कारण मैं टिकट नहीं खरीद पाता और नतीजा यह हुआ कि मुझे आपके टिकट कलेक्टरों की डांट का सामना करना पड़ा। दादर में आपकी महिला टिकट कलेक्टरों ने हमारी कठिनाइयों को समझने के बजाय हमें सबसे अपमानजनक तरीके से परेशान किया है और इसने हमारे मन पर एक दाग छोड़ दिया है।यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके लोग कितने बुरे हो सकते हैं, तो आप एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं जिसे हम तथ्यों को समझा सकें।

मुझे पता है कि सेंट्रल लाइन पर किसी भी रेलवे पुलिस स्टेशन के मामलों को संभालने वाले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को नागपुर से इगासुरी तक प्रथम श्रेणी का मुफ्त पास मिलता है।यहां तक कि ऐसे मजिस्ट्रेट से जुड़े

कर्मचारियों को भी मुफ्त पास मिलते हैं।हमशनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिन भी रेलवे का काम देखते हैं.तो क्या हम ऐसी आपात स्थिति के दौरान समय पर अपने न्यायालय पहुंचने के उद्देश्य से कम से कम लोकल ट्रेनों के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में खड़े होने के हकदार नहीं हैं?कृपया इस मामले में तत्काल टिकट संग्राहकों को आवश्यक निर्देश देकर कार्रवाई करें ताकि हमें आपके टिकट संग्राहकों द्वारा इस मामले में अपमानित न होना पड़े और जुर्माना न भरना पड़े।

यदि आपकी राय नकारात्मक है, कि यह छोटा सा शिष्टाचार भी हमारे साथ नहीं निभाया जा सकता, तो कृपया मुझे बताएं, ताकि मैं ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहूँ। आपकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया की अत्यधिक सराहना की जाएगी।"

22. उपरोक्त पत्र और यह तथ्य कि वह मुलुंड और दादर स्टेशन के बीच अपनी यात्रा के लिए कोई टिकट या पास नहीं दिखा सकी, स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करती है कि 5.12.1997 को उसने बिना टिकट के यात्रा की थी।

23. उपरोक्त स्थिति के बावजूद, उन्होंने महाप्रबंधक, मध्य रेलवे, मुंबई को एक पत्र लिखा था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कभी-कभीवह समय की कमी के कारण टिकट खरीदने में असमर्थ होती हैं, जिसके लिए उन्हें टिकट कलेक्टरों द्वारा परेशान किया जाता है, इसलिए, ऐसी आपात स्थिति के दौरान समय पर अदालत पहुंचने के उद्देश्य से उसे स्थानीय ट्रेनों के प्रथम श्रेणी डिब्बे में मुफ्त यात्रा प्रदान की जानी चाहिए।

24. 5.12.1997 को घटना के तुरंत बाद लिखा गया एक पत्र स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उसने 5.12.1997 को बिना टिकट यात्रा की थी और उसने उससे टिकट की मांग की थी क्योंकि वह एक मजिस्ट्रेट है और उसने टिकट कलेक्टरों के खिलाफ शिकायत की थी। 5.12.1997 के आरोपों के ज्ञापन में अपीलकर्ता के खिलाफ लगाया गया अपराध उसके स्वयं के दिखाने पर स्थापित होता है और इसलिए, जांच अधिकारी का इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित था कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हुए हैं।

25. अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वह यह है कि क्या जांच अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को दंडित करने की सिफारिश करना उचित था।

26. हमने उपरोक्त मुद्दे को नियमों के प्रावधानों के आलोक में भी देखा है।नियमों के नियम 8(25)(ई) में एक जांच अधिकारी को मामले के तथ्यों के आधार पर सजा देने की सिफारिश करने की अनुमति दी गई है। हालाँकि, वह प्रावधान जिसे पहले के नियमों में जगह मिली थी, वर्ष 1997

में नियमों में लाए गए संशोधन द्वारा पूर्वोक्त नियमों से हटा दिया गया था। उस संदर्भ में, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि ए जांच अधिकारी द्वारासजा के संबंध में सिफारिश की गई है, संपूर्ण निष्कर्ष दूषित हैं और इसलिए रद्द किए जाने योग्य हैं।

27. हालाँकि, हम उपरोक्त प्रस्तुतियाँ स्वीकार करने में असमर्थ हैं। रिकॉर्ड देखने पर, हम पाते हैं कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर विचार किया और उसके बाद एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ता अपने खिलाफ लगाए गए कदाचार के आरोपों का दोषी है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, एक बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति केवल उन पर ही लगाई जा सकती थी और परिणामस्वरूप ऐसी सजा देने का निर्णय लिया गया।अंततः अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाने के साथ ही संपूर्ण अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त हो गई।

28. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि दी गई उपरोक्त सजा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुपात से अधिक है और उसे कम से कम उसकी पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए जो कि उसे अनुमति दिए जाने पर भुगतान किया जा सकता है। अगले दो साल तक काम करें.अपीलकर्ता

के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता ने 8 साल की सेवा पूरी कर ली है और यदि उसने दो साल और काम किया होता, तो वह अन्य 10 साल की सेवा के अलावा पेंशन की हकदार होती।

29. हालाँकि, हम उपरोक्त तर्क को इस साधारण कारण से स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि हम शायद सजा की मात्रा में तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जब हम पाते हैं कि दी गई सजा अदालत की अंतरात्मा को चौंकाने वाली है। यह न्यायिक अधिकारी का मामला है जिसे एक न्यायिक अधिकारी बनने के लिए गरिमा और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करना आवश्यक था। एक न्यायिक अधिकारी को त्रुटिहीन आचरण दिखाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम होना चाहिए।मौजूदा मामले में, उसने न केवल तीन बार रेलवे डिब्बे में बिना टिकट यात्रा की, बल्कि उन टिकट कलेक्टरों के खिलाफ भी शिकायत की, जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, रेलवे अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन परिस्थितियों में हमें समझ नहीं आता कि उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा कैसे दी जा सकती है। यह उसके विरुद्ध कथित अपराध से असंगत कहा जाएगा। कानून के शासन द्वारा शासित देश में, न्यायिक अधिकारियों सहित कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। वस्तुतः न्यायिक अधिकारी के रूप में उन्हें प्रत्येक आचरण में गरिमा का सतत पहलू प्रस्तुत करना होता है। यदि कानून के शासन को हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तत्वावधान में प्रभावी ढंग से और कुशलता से कार्य करना है, तो न्यायाधीशों से अपेक्षा

की जाती है कि, बल्कि, उन्हें खुद को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करके एक कुशल और प्रबुद्ध न्यायपालिका का पोषण करना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि एक न्यायाधीश लगातार सार्वजनिक निगरानी में रहता है और समाज एक न्यायाधीश से आचरण और ईमानदारी के उच्च मानकों की अपेक्षा करता है। न्यायिक कार्यालय, सार्वजनिक विश्वास का कार्यालय होने के नाते, समाज को यह अपेक्षा करने का अधिकार है कि एक न्यायाधीश को प्रत्येक कार्य में औचित्य के सबसे सटीक मानकों को बनाए रखते हुए उच्च सत्यनिष्ठा, ईमानदार और नैतिक दृढ़ता वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए, एक न्यायाधीश का आधिकारिक और व्यक्तिगत आचरण औचित्य और ईमानदारी के उच्चतम मानक के अनुरूप होना चाहिए। जाहिर है, आचरण का यह मानक दूसरों के लिए स्वीकार्य या स्पष्ट समझे जाने वाले मानकों से ऊंचा है। दरअसल, मौजूदा मामले में, एक न्यायिक अधिकारी होने के नाते, यह उनके हित में था कि वह खुद को शालीन और गरिमापूर्ण तरीके से पेश करें। यदि उसने जानबूझकर इन उच्च और सख्त मानकों से हटना चुना है, तो वह उचित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

30. हम अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हैं। हमें उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय का कारण बताते हुए निकाले गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है, जिससे हम पूरी तरह सहमत हैं और औचित्य पाते हैं।

31. इसलिए, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे बिना किसी लागत के खारिज कर दिया जाता है।

अपील खारिज |

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी यतिन्द्र चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।